



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85]
No. 85]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 1983/ज्येष्ठ 3, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 1983/JYAISTHA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 18-आई टी सी (पी एन)/83

नई दिल्ली, 24 मई, 1983

विषय : अप्रैल, 1983—मार्च, 1984 के लिए आयात-निर्यात नीति

मिनिस्टर सं० आई पी सी/3/1/83—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक
सूचना सं० 10-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 15 अप्रैल, 1983 के अधीन
प्रकाशित अप्रैल, 1983—मार्च, 1984 की आयात निर्यात नीति (जिल्द-1)
की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. 1983-84 की आयात निर्यात नीति (जिल्द-1) में निम्नलिखित
संशोधन उचित स्थानों पर किए जायेंगे—

क्रम	आयात-निर्यात	संशोधन
सं०	नीति	
	(जिल्द-1)	
1983-		
84 की		
पृष्ठ सं०		

1	2	3	4	5
1.	8-9	अध्याय-6, वास्त- विक उपायोक्तियों (औद्योगिक) द्वारा कच्चे माल,	(1) उप-पैरा 31(2) की 7वीं पंक्ति में आंकड़े "10" को "1.5" पढ़ा जाएगा।	

1	2	3	4
संघटकों, उपभोक्त्यों और फालतू पुर्जों का आयात पैरा 31	(2) उप-पैरा 31(2) की 15वीं पंक्ति में 'एक लाख' शब्द को "1.5 लाख" पढ़ा जाएगा		
	(3) उप-पैरा 31(2)(घ) की चौथी पंक्ति में "एक लाख रुपए के बाजार" शब्द हटा दिए जायेंगे।		
	(4) उप-पैरा 31(2)(ङ) की 5वीं और छठी पंक्ति में "1 लाख रुपए के बजाए" शब्द और आंकड़े हटा दिए जायेंगे।		
	(5) उप-पैरा 31(3) की दूसरी पंक्ति में "1 लाख" आंकड़े को "1.5 लाख" पढ़ा जाएगा।		
2. 11	पैरा 38	वर्तमान उप-पैरा 38(2) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा और भी जोड़ा जाएगा :—	
		"(2-क) उपर्युक्त उप-पैरा 3(1) (घ) के अधीन वास्तविक उपयोगिता (औद्योगिक) को जारी किए गए नूरक लाइसेंस उनके कुल मूल्य के भीतर परिशिष्ट 3 और 6 के अंतर्गत आने वाली मशीनों के आयात के लिए	

1	2	3	4	1	2	3	4
							अधीन आयात के लिए अलग अहस्तामरणीय लाइसेंस जारी करेंगे।
						(4)	उपर्युक्त उप-पैरा (2) और (3) की सुविधाओं का प्राधिकृत उत्पादन के लिए ही विनिर्माता निर्यातक द्वारा ही उपयोग किया जाएगा।
3	पृष्ठ 39	अध्याय-17	(1) वर्तमान पैरा 134 को "134(1)" के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।	5.	43	अध्याय 17, पंजी- वर्तमान उप-पैरा 142(1)(च) के बाह्य कृत निर्यातक, पैरा 142	अधीन निम्नलिखित उप-पैरा को जोड़ा जाएगा -
		पंजीकृत निर्यातक आयात-प्रतिपूर्ति की सीमा, पैरा 134	(2) यथा पुनर्संख्यांकित वर्तमान पैरा के बाद निम्नलिखित उप-पैरा को और आगे जोड़ा जाएगा				"(छ) वह विनिर्माता निर्यातक जिसने चर्चीता उत्पादों के अपने उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत जो न्यूनतम 5 लाख रुपए के अधीन है, 2 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में निर्यात किया है, सो उसे उपर्युक्त उप-पैरा (क) के अंतर्गत 1983-84 में 50 लाख रु० (लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य) के मूल्य तक मशीनरी के आयात करने की अनुमति दी जा सकती है। उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें समान रूप से लागू होंगी।
			"(2) पैरा 224 में दिए गए प्रावधानों का उल्लेख नए उत्पादों या मए बाजारी के संबंध में किया जाएगा।				(ज) वह विनिर्माता, निर्यातक जो उपर्युक्त उप-पैरा (क) और (छ) के अंतर्गत मशीनरी का निर्यात करने का हक्कुक है सो उसे उस मशीनरी का निर्यात करने की अनुमति, निर्धारित शर्तों के अधीन उसके खूद के वैध आर ई पी लाइसेंस (लाइसेंसों) के मद्दे अथवा लागू आयात नीति के अनुसार, हस्तांतरण द्वारा प्राप्त किए गए वैध आर ई पी लाइसेंसों के मद्दे दी जा सकती है। अन्य यथा निर्धारित शर्तें लागू होंगी। जहां तक उप-पैरा (क) और (छ) में आने वाले संबंधित विनिर्माता निर्यातकों का संबंध है, यह सुविधा उप पैरा (घ) में दिए गए प्रावधानों की दृष्टि से होगी।
4.	39	अध्याय 17 पंजी- कृत निर्यातक, पैरा 136(2)	(1) चौथी पंक्ति में आंकड़े "10" के स्थान पर "20" पड़ा जाएगा।				
			(2) वर्तमान उप-पैरा 136(2) के पश्चात निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा				
			"(3) उपर्युक्त उप-पैरा (2) में 10 लाख रुपए मूल्य तक के तकनीकी डिजाइन के आयात के लिए यथा निर्धारित न्यूनतम निर्यात निष्पादन वाले विनिर्माता निर्यातकों को उपलब्ध सुविधा का उपयोग नीति के अनुसार उनके निर्यातों के आधार पर उनके द्वारा प्राप्त उनके वैध आर ई पी लाइसेंसों के मद्दे या वे आयात नीति के अनुसार हस्तांतरण द्वारा प्राप्त किए गए वैध आर ई पी लाइसेंस के मद्दे किया जा सकता है। उपर्युक्त उप-पैरा (2) के अर्थात इस उद्देश्य के लिए लाइसेंस प्राधिकारी आर ई पी लाइसेंसों पर पृष्ठांकन करते समय वास्तविक उपयोगिता शर्तें भी लगाएंगे। जहां विनिर्माता-निर्यातक आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार विपयाधीन आर ई पी लाइसेंसों के शेष मूल्य का हस्तांतरण करना चाहता है, तो लाइसेंस प्राधिकारी से अनुरोध करने पर संबंध मुख्य आर ई पी लाइसेंस के मूल्य में तदनु रूप कमी करके, उपर्युक्त उप-पैरा (2) के	6.	44	अध्याय 17, पंजी- (i) वर्तमान उप-पैरा को "148(1) कृत निर्यातक आर ई पी के रूप में पुनःसंख्यांकित किया लाइसेंसों के पृष्ठांकन जाएगा। के लिए विशेष (ii) यथा पुनःसंख्यांकित उप पैरा (i) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा को अनुरोध पैरा 148 और आगे जोड़ा जाएगा :	
							"(2) वे विनिर्माता निर्यातक जो पूर्ण रूप से निर्यात करने के लिए उत्पादन कर रहे हैं, किन्तु वे शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकको की योजना के अंतर्गत इस प्रकार अनुमोदित नहीं किए जा रहे हैं तो उन्हें लागू आयात नीति के अनुसार उनके

1	2	3	4	1	2	3	4
			<p>द्वारा प्राप्त किए गए वैध आर ई पी लाइसेंस के समस्त मूल्य के भीतर इस नीति के परिशिष्ट 3, 6 या 8 में आई हुई किसी भी मद का आयात के लिए अनुमति दी जा सकती है।</p> <p>ऐसे आयात इस शर्त के अधीन होंगे कि आयात की जाने वाली वे मदें जो विनिर्माण-निर्यातक द्वारा उनके अपने स्वयं के एकक में उत्पादन के लिए अपेक्षित हैं और सम्पूर्ण उत्पादन का निर्यात किया जाएगा। उनकी रिपोर्ट संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को तैयारिक आधार पर संबंधित निमाही अवधि के समाप्त होने के एक मास के भीतर प्रत्येक आयातित मद का लागत-व्रीमा-भावा मूल्य और मात्रा और निर्यातित मात्रा के जहाज पर्यन्त निष्पन्न मूल्य के साथ मदवार ब्याज और मात्रा का ब्यौरा देने हुए विधिवत भेजी जाएगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पृष्ठांकन के लिए अनुरोध सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किए जाएंगे। पृष्ठांकन किए जाने वाले आर ई पी लाइसेंस की वैधता अवधि-में जिस तिथि का मध्याह्न लाइसेंस प्राधिकारी का पृष्ठांकन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, उससे कम से कम 3 मास की अप्रत्यक्ष अवधि में रहनी चाहिए।</p>				
7 80	परिशिष्ट 1	वर्तमान विवरण के अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि स 4	को जोड़ा जाएगा —				
	(10) माइक्रो मशीन माइक्रो कुकिंग/मिस्सिंग उपस्कर सहित		“माइक्रो जीरो दविस्ट फिनामेट यार्न के अतिरिक्तता।”				
8 92	परिशिष्ट 2	वर्तमान प्रविष्टि स 17 के पश्चात् उप-शीर्षक स 12	निम्नलिखित नई प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा — “(18) वैश फैंड हार्ड स्पीड लैटर प्रेम रोटर एंड आफ सेट रोटरों प्रिंटिंग मशीनें जिनकी क्षमता 35,000 कम्पोजिट इम्प्रेशन या प्रतियां प्रति घंटे से अधिक हैं।				
9 133	परिशिष्ट 5	उप-प्रविष्टि स 471 (18)	इस उप-प्रविष्टि को हटाया जाएगा।				
10 277	परिशिष्ट 21	वर्तमान पैरा 6 के पश्चात् मुक्त व्यापार क्षेत्र (काइला और सांताक्रुज) में स्थित एकको द्वारा पंजीकृत	<p>पैरा को और आगे जोड़ा जाएगा — “7 वैश सामान्य मुद्रा क्षेत्र आयात लाइसेंस की मदों के भारत में माल की बिक्री</p> <p>(1) भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र में</p>				
			माल, कच्चा विनिर्मित माल को वैश सामान्य मुद्रा सामग्रियां, सफ्टको अंत के आयात लाइसेंस के मदों परेशु कायनू पुर्जों आदि टेरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति दी जा के आयात के सकती है। ऐसी बिक्री 1983-84 के लिए क्रियाविधि। दौरान मुक्त व्यापार क्षेत्र से सम्बद्ध एकक द्वारा ऐसी मद के उत्पादन का का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
			(ii) सम्बद्ध मुक्त व्यापार क्षेत्र के विकास आयुक्त की पूर्ण अनुमति स ही बिक्री की जाएगी। अतः परेशु टेरिफ क्षेत्र में अपने माल को बेचने के इच्छुक एकको को विकास आयुक्त स सम्पर्क करना चाहिए। इसे वैश सामान्य मुद्रा क्षेत्र लाइसेंस के मदों परेशु टेरिफ क्षेत्र में सन्निहित की जाने वाली मद की मात्रा और 1983-84 के दौरान उस तिथि को एकक द्वारा उत्पादित उसी मद की कुल मात्रा का भी बर्ताना चाहिए जिससे विकास आयुक्त यह सत्यापित कर सकें कि बिक्री एकक द्वारा पहले से ही विनिर्मित उत्पादन से 25% से अधिक ता नहीं है।				
			(iii) विकास आयुक्त से अनुमति लेने के पश्चात् वैश सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लाइसेंस के मुद्रा बिक्री की जा सकती है। क्षेत्र से बाहर माल की अनुमति देने से पूर्व विकास आयुक्त सम्बद्ध आयात लाइसेंस के नाम डालेगा। इस सीमा तक आयात लाइसेंस आगे के आयात के लिए अर्पित हो जाएगा।				
			(iv) परेशु टेरिफ क्षेत्र में माल के क्रेता को ऐसे उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क और अन्य ऐसे शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा जो विपदाधीन माल पर लगाए जा सकते हैं। यह राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० 13/83 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 11 फरवरी, 1983 और मुक्त व्यापार क्षेत्र में विनिर्मित माल की “परेशु टेरिफ क्षेत्र” में बिक्री से सम्बद्ध उनके द्वारा समय-समय पर जारी की गई ऐसी अन्य अधिसूचनाओं/अनुदेशों के अधीन होगा।				
			3 वाणिज्य भद्रालय का सार्वजनिक सूचना सं० 11-आईटीसी/पीएन/83, दिनांक 15 अप्रैल, 1983 के अंतर्गत प्रकाशित आयात-निर्यात क्रियाविधि रेन्डबुक 1983-84 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। रेन्डबुक में निम्नलिखित संशोधन किए गए समझे जाएंगे —				
			(I) अध्याय—4 में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे —				
			(क) एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइन्स के माध्यम से आयात के संबंध में वर्तमान पैरा “89” को पैरा “89(1)” के रूप में पुनः संशोधित किया जाएगा।				

(ख) पुन. सञ्चालित वर्तमान उप-पैरा (1) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा :—

“(II) ये प्रावधान भारतीय जलयानों के माध्यम से किए गए आयातों के लिए भी लागू होंगे।”

(2) पृष्ठ 36 पर अध्याय—6 “सरणीबद्ध करना” में वर्तमान उप-पैरा 155(2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा —

“(2) यदि किसी वास्तविक उपयोक्ता ने अपनी मांग सबद्ध सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी से पंजीकृत कराई है और सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी वास्तविक उपयोक्ता द्वारा अधिम धनराशि चुका देने की तिथि से तीन महीने के भीतर माल का संभरण नहीं करती है तो वास्तविक उपयोक्ता उसी माल की उस मात्रा के 25% तक की सीमा तक के लिए संबद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी से सीधे आयात लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है जो मात्रा पिछले वित्तीय वर्ष में सरणीबद्ध करने वाले अधिकरण ने उसका आवंटित की थी, यह मात्रा इस शर्त के अधीन होगी कि वह मूल्य में अधिक से अधिक 1 00 लाख रुपए (लागत-बोना-भाडा) हो और उस निर्धारित योजना के अंतर्गत आवंटन के लिए अनुमेय मात्रा के भीतर हो जिसके संबंध में यथा-पूर्वोक्त सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी द्वारा उसने अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना संभरण न किया गया हो। सीधे ही आयात लाइसेंस के लिए ऐसे आवेदनपत्रों के साथ आवेदक फर्म/कम्पनी के बरिष्ठ कार्यकारी से एक घोषणापत्र सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी को अधिम धनराशि चुकाने की तिथि, पंजीकृत कराए गए माल का विवरण और उसकी मात्रा निविष्ट करते हुए और स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख करते हुए होना चाहिए कि सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी ने अधिम धनराशि चुकाने के तीन महीने के भीतर माल का संभरण नहीं किया है। उक्त घोषणापत्र में उस माल का विवरण और उसकी मात्रा का भी उल्लेख होना चाहिए जो सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी ने आवेदक फर्म को पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित किया था और आवंटन के लिए देय माल की वह मात्रा भी होनी चाहिए जिसके लिए संभरण में विलम्ब किया गया है। लेकिन यह सुविधा उपर्युक्त पैरा 150 और 151 में सूचीबद्ध मबो और आयात निर्यात नीति, 1983-84 (जिल्द-1) के परिशिष्ट-9 की मबा के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

(3) परिशिष्ट-31 में वर्तमान पैरा 6 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा —

“7 इस परिशिष्ट में दिए गए प्रावधान भारतीय जलयानों के माध्यम से किए गए आयातों के लिए भी निर्धारित शर्तों के अधीन लागू होंगे।”

[सं० मि० आईपीसी/3/1/83]

वि० के० शुक्ल, सैन्य सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE 18-ITC(PN)/83

New Delhi the 24th May, 1983

Subject : Import & Export Policy for April, 1983-March, 1984.

No. IPC/3/1/83 :—Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1983 March, 1984 (Vol I), published

under the Ministry of Commerce Public Notice No 10-ITC (PN)/83 dated the 15th April, 1983

2. The following amendments shall be made at appropriate Place in the Import and Export Policy (Vol I) for 1983-84.

Sl No of Import & Export Policy (Vol. I) 1983-84	Page No	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 8—9		Chapter 6, Import of Raw Materials, Components, Consumables and Spares by Actual Users (Industrial) Para 31	(i) In sub-para 31(2), in 7th line, the figure “1 0” shall read “1 5”. (ii) In sub-para 31(2), in 15th line, the words “one lakh” shall read “1 5 lakhs”. (iii) In sub-para 31(2) (d), in the 4th line, the words “instead of Rs. one lakhs” shall be deleted (iv) In sub-para 31(2)(g), in the 5th and 6th lines, the words & figure “instead of Rs 1 lakh” shall be deleted (v) In sub-para 31(3), in the second line, the figure and word “1 lakh” shall read “1 5 lakhs”
2. 11		Para 38	After the existing sub-para 38(2), the following further sub-para shall be added — “(2-A) Supplementary licences issued to Actual Users (Industrial) under Sub-para 38 (1)(d) above, will also be valid, within their overall value, for import of items appearing in Appendix 3 or 6 subject to the condition that the import of a single item does not exceed Rs 1 5 lakhs (cif) in value.
3	Page 39	Chapter 17 Registered Exporters, Extent of Import Replenishment, para 134	(i) The existing para 134 shall be re-numbered as “134 (1)” (ii) After the existing sub-para (1) as renumbered, the following sub-para shall be added :— “(2) The provisions made in para 224 may be referred to in

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
			respect of exports of new products or to new markets."				question, "under the provisions of the import policy, the licensing authority may, on request, issue a separate non-transferable licence for import under sub-para(2) above, by corresponding reduction in the value of the concerned main REP licence.
		(3)	In respect of exports made through Indian vessels, the registered exporter will be eligible for REP licence under the import policy for Registered Exporters in accordance with the provisions made in Appendix 17, at the rate of import replenishment higher than 10% of the normal rate, i.e. 11% instead of the normal 10% and so on."				(4) The facilities in sub-para (2) and (3) above will be used by the manufacturer-exporter only for the purpose of authorised production.
4.	39	Chapter 17, Registered Exporters, para 136(2)	(i) In the 4th line, the figure "10" shall read "20". (ii) After the existing sub-para 136(2), the following new sub-para shall be added :— "(3) The facility for import of technical designs etc. upto Rs. 20 lakhs in value, available in sub-para (2) above to manufacturer-exporters having a minimum export performance as laid down, can be availed of by them either against their own valid REP licences obtained on the basis of their exports, as per policy, or against valid REP licences acquired by transfer in accordance with the import policy. The licensing authority, while making an endorsement on REP licence for this purpose under sub-para (2) above shall, also impose Actual User condition. Where the manufacturer-exporter intends to transfer the balance value of the REP, licence, in	5.	43	Chapter 17, Registered Exporters, Para 142.	After the existing sub-para 142(1)(f), the following further sub-para shall be added :— "(g) A manufacturer-exporter who exported at least 50% of his production of select products, subject to a minimum of Rs. 5 lakhs (FOB), in any of the two previous financial years, may be allowed to import machinery, under sub-para (a) above, upto a value of Rs. 50 lakhs (CIF) in 1983-84. Other conditions mentioned in sub-para (a) above will equally apply. (h) A manufacturer-exporter intending to import machinery under sub-para (a) and (g) above, may be allowed to import the same subject to prescribed conditions, against his own valid REP licence(s) or against valid REP licence(s) acquired by him, by transfer, in accordance with the import policy in force. Other conditions as laid down will apply. This facility will be in relaxation of the provision made in sub-para (d) above, in so far as manufacturer-exporters covered under sub-para (a) and (g) are concerned."

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
6.	44	Chapter 17 Registered Exporters, Special requests for endorsement on REP licences Para 148	<p>(i) The existing sub-para shall be re-numbered as "148(1)".</p> <p>(ii) After the existing sub-para (1) as re-numbered, the following further sub-para shall be added :—</p> <p>“(2) Manufacturer-exporters producing exclusively for exports but, not approved as such under the scheme of 100% export oriented units, may be allowed to import any item appearing in Appendices 3, 6 or 8 of this policy, within the overall value of valid REP licence acquired by transfer, in accordance with the import policy in force. Such import shall be subject to the condition that the items to be imported are those as are required by the manufacturer - exporter for production in his own unit, and the entire production shall be exported. Reports there of shall be duly furnished to the licensing authority concerned on a quarterly basis, with in one month of the expiry of the concerned quarterly period, giving the description of each item imported with its CIF value and quantity, and the FOB value of goods exported with their description and quantity itemwise. Requests for endorsement under this provision will be entertained by the regional licensing authorities concerned subject to prescribed conditions. The REP licence sought to be endorsed should have unutilised balance of at least 3 months in its period of validity as on the</p>				date on which request for endorsement is received by the concerned licensing authority.
7.	80				Appendix-I Entry No. 4(10) Sizing machine including size cooking/mixing equipment.		The following shall be added at the end of the existing description :— “except for sizing zero twist filament yarn”.
8.	92				Appendix-2 Sub-Heading No. 12 Printing Machinery.		After the existing entry No. 17, the following new entry shall be added :— “(1b) Web fed high speed letter press rotary and off set rotary printing machines having output of more than 35,000 composite impressions or copies per hour.”
9.	133				Appendix-5 Sub-Entry No. 47(18)		This sub-entry shall be deleted.
10.	277				Appendix-21 Procedure for import of Capital Goods, Raw Materials, components, spares etc by units located in Free Trade Zones (Kandla & Santacruz)		<p>After the existing para 6, the following further para shall be added :—</p> <p>“7. Sale of goods in India against valid General Currency Area import licences.</p> <p>(1) Goods manufactured in Free Trade Zone in India may be allowed to be sold in the Domestic Tariff Area against valid General Currency Area import licences. Such sale shall not exceed 25 per cent of production of the same item by the unit concerned in the Free Trade Zone during 1983-84.</p> <p>(2) The sale shall be effected only with the prior permission of the Development Commissioner of the concerned Free Trade Zone. The unit desiring to sell their goods to the Domestic Tariff Area should, therefore, approach the Development Commissioner. It should also indicate the quantity of the item sought to be supplied in DTA against valid GCA licence and the total quantity of the same item produced by the unit,</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			as on date, during 1983-84, to enable the Development Commissioner to verify that the proposed sale is not exceeding 25 percent of the production already turned out by the unit.
			(3) After obtaining permission from the Development Commissioner, the sale can be effected, against valid GCA licence. The Development Commissioner will debit the connected import licence before the goods are allowed to be taken out of the Zone. To this extent, the import licence shall cease to be valid for further imports.
			(4) The purchaser of the goods in the Domestic Tariff Area shall be liable to pay the excise duty, sales tax and such other taxes as may be leviable on the goods in question. This shall be subject to Notification No. 13/83-Central, Excise dated the 11th February, 1983 issued by the Department of Revenue, New Delhi and such other notifications or instructions as may be issued by them, from time to time in regard to the sale of goods manufactured in a Free Trade Zone, into the Domestic Tariff Area."
			3. Attention is also invited to the Hand Book of Import-Export Procedures, 1983-84 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 11-ITC (PN)/83 dated the 15th April, 1983. The following amendments shall be deemed to have been made in the Hand Book :-
			(i) In Chapter IV the following changes shall be made :-
			(a) The existing para "89" regarding imports through Air India/Indian Airlines, shall be re-numbered as "89(1)".
			(b) After the existing sub-para (1), as renumbered, the following sub-para shall be added :-
			"(2) These provisions will also apply to imports made through Indian Vessels."
			(ii) The existing sub-para 155(2) in Chapter VI, "Canalisation", at page 36, shall be substituted by the following :-
			"(2) If an Actual User has registered his demand with the canalising agency concerned, and the canalising agency does not supply the material within the 3 months from the date the Actual User has paid the earnest money, the Actual User may apply for direct import licence to the regional licensing authority concerned to the extent of 25% of the quantity of the same material allocated to him by the canalising agency in the previous financial year, subject to a maximum of Rs. 1.00 lakhs in value (CIF), and within the quantity due for allotment under the prescribed scheme, in respect of which the supply has not been made by the canalising agency as aforesaid, without having to obtain "No objection Certificate" from the canalising agency. Such application for direct import licence should be accompanied by a declaration of a senior executive of the applicant firm/company, giving the date of payment of earnest money to the canalising agency, the description of the material registered and its quantity, and stating, in clear terms, that the canalising agency has not supplied the material within three months of the payment of the earnest money. The declaration should also mention the description and the quantity of the same material allocated to the applicant firm/company by the canalising agency in the previous financial year, and the quantity of the material due for allotment in respect of which the supply has been delayed. This facility will not, however, be available for items listed in para 150 and 151 above and for items in Appendix 9 of Import-Export Policy, 1983-84.
			(iii) In Appendix 31, after existing para 6, the following further para shall be added :-
			"7. The provisions made in this Appendix will also apply to imports made through Indian vessels, subject to the conditions laid down."

